ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगा

सरकारी पैसे पर सरकार से ब्याज लेने के चलन पर लगी रोक

कन्हैया लोधी

भोपाल, 27 जुलाई. पैसा यदि कमाई का है तो फिर उस पर ब्याज लेना जायज है, लेकिन यदि पैसा भी उसी का है, जिससे ब्याज लिया जा रहा है, तो फिर भला ऐसे राशि पर ब्याज लेने की क्या तुक? कमोबेश इसी तरह के चलन पर अब वित्त विभाग की नजर पड़ गई है और इस नजर का असर ये है कि विभाग ने निगम, मंडल, प्राधिकरण, सोसायटियों द्वारा सरकारी पैसे पर ही सरकार से ब्याज लेने के चलन पर सख्ती से रोक लगा दी है.

इतना ही नहीं मूलधन पर ब्याज लेना तो समझ आता है, लेकिन मूलधन के साथ ब्याज पर भी ब्याज लिया जा रहा था, ऐसे में वित्त विभाग ने इस पर भी कैंची चला दी है. हाल ही में वित्त विभाग ने सभी विभागों, विभागाध्यक्ष, कलेक्टरों को बाकायदा पत्र लिखा है. ये पत्र मप्र कोषालय संहिता 2020 के तहत विशेष जमा खातों में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर के निर्धारण के संबंध में है. इस पत्र में वित्त विभाग ने राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों जैसे निगम, मंडल, स्थानीय निकाय, नगरीय एवं ग्रामीण प्राधिकरण और सोसायटियों द्वारा कोषालय में संधारित किए जाने वाले विशेष जमा खातों के लिए ब्याज दरों को लेकर नए निर्देश दिए हैं.

वित्त विभाग ने सभी विभागों को लिखे पत्र में साफ कर दिया है कि अब विशेष जमा खातों में संधारित राशि पर 2.50 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से ही साधारण ब्याज मिलेगा. यानी बाजार दर या फिर बैंकों के सामान्य दरें इस पर लागू नहीं होंगी. यह ब्याज भी 6 माह के अंतराल पर दिया जाएगा. किसी भी स्थिति में ब्याज पर ब्याज नहीं दिया जाएगा. यानी अब ब्याज को मूलधन की राशि से अलग कर ब्याज की गणना की जाएगी. साफ है कि अब केवल मूलधन पर ब्याज मिलेगा.

वित्त विभाग के नए निर्देशों के मुताबिक अब ब्याज केवल संबंधित संस्थानों के स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त एवं जमा की गई राशि पर ही मिलेगी. केंद्र सरकार या राज्य सरकार की संचित निधि से प्राप्त किसी भी राशि या योजनाओं के फंड पर कोई ब्याज देय नहीं होगा. राशि जमा करते समय संस्थान के अधिकृत प्रशासक के लिए यह जरुरी होगा कि वह ऐसा प्रमाणीकरण दे, कि जमा की जा रही राशि का स्त्रोत राज्य या केंद्र की संचित निधि नहीं है.

30 दिन से कम अवधि पर नहीं मिलेगा ब्याज

वित्त विभाग के नए निर्देशों में कहा गया है कि विशेष जमा खाते से धन निकासी, आहरण के समय आहरित की जा रही राशि पर उसके जमा दिनांक से आहरण दिनांक तक की अवधि के लिए सिस्टम द्वारा स्वत: ब्याज की गणना की जाएगी. इसी तरह विशेष जमा खातों में राशि जमा होने के बाद न्यूनतम 30 दिनों की अवधि पूर्ण होने पर ही ब्याज की पात्रता होगी. यानी साफ है कि 30 दिन से कम अवधि के जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा.

गुरू पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होंगे सीएम

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर 29 जुलाई को उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय में आयोजन किया जायेगा. मुख्यमंत्री द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी की बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत या उससे अधिक परिणाम देने वाले शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों का सम्मान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मिशन बुनियाद परियोजना का शुभारंभ और स्कूल शिक्षा विभाग के नवनियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा.

एक नजर में

दूध और मावे के 8 नमूने जांच के लिए भोपाल भेजे

धार. जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध और मावे के आठ नमूने एकत्र कर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे हैं. बिना पंजीयन डेयरी संचालन के मामलों में तीन संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया, एक डेयरी को सील कर दिया गया. खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष खेडकर ने बताया कि 24 और 25 जुलाई को जिले के ग्रामीण एवं तहसील क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया. इस दौरान मां मोगल दूध डेयरी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, लवेश दूध-दही भंडार तथा दूध परिवहन कर रहे अरुण गेहलोत से दूध के नमूने लिए.

मुरैना में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या

मुरैना. जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और उसके सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए. पुलिस सूत्रों के अनुसार यह घटना ग्राम उत्तमपुरा में रविवार देर रात हुई. मृतका की पहचान विमला पत्नी बाबू सिंह सिंकरवार के रूप में हुई है. बताया गया कि उनके पति और बच्चे ग्वालियर में रहते हैं, जबकि वह लगभग दस दिन पहले अकेले गांव आई थीं. घटना के समय वह घर में अकेली थीं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार देर रात अज्ञात बदमाश घर में घुसे और धारदार हथियार से उनका गला रेतकर हत्या कर दी.

इंजीनियरों को मिली सीवरेज ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 27 जुलाई. नगरीय विकास एवं आवास विभाग के 40 सदस्यीय इंजीनियरों के दल को नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी में एक दिवसीय ट्रेनिंग दी गई.

कैपेसिटी बिल्डिंग इन द फील्ड ऑफ सीवरेज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी फॉर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर आयोजित प्रशिक्षण का मुख्य ध्येय राज्य के तकनीकी अधिकारियों को तरल अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों से सुसज्जित करना है. प्रशिक्षण सत्र में अभियंताओं को घरेलू प्रणालियों में अपशिष्ट जल के सुचारू प्रबंधन तथा त्रुटिरहित डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने की प्राविधिक बारीकियों से अवगत कराया गया.

> प्रशिक्षणार्थियों के व्यावहारिक ज्ञानवर्धन के लिए दल को अंबाझिरी स्थित 3.2 एमएलडी क्षमता के इको सीडब्ल्यू मल-जल शोधन संयंत्र का स्थल भ्रमण कराया गया. किफायती वेटलैंड तकनीक पर आधारित इस संयंत्र के माध्यम से अभियंताओं ने कम लागत में पर्यावरण-अनुकूल एवं प्रभावी सीवरेज ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से समझा. शहरी विकास को समावेशी एवं सुगम्य बनाने के दृष्टिकोण से दल को नागपुर स्थित दिव्यांग पार्क का विशेष अध्ययन भ्रमण भी कराया गया, जिससे मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में दिव्यांगजनों की सहूलियत के लिए सुगम्य एवं उन्नत अधोसंरचना का विकास किया जा सके.

41.58 लाख गबन मामले में फरार शाखा प्रबंधक गिरफ्तार

खरगोन, 27 जुलाई. खरगोन जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठीबगांव शाखा में 41.58 लाख रुपये के गबन के मामले में फरार चल रहे शाखा प्रबंधक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

जैतापुर थाना प्रभारी सुदर्शन कलोसिया ने बताया कि शाखा प्रबंधक राजेश राठौर को सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उसे बैंक की ठीबगांव शाखा में 41 लाख 58 हजार 95 रुपये के गबन के मामले में आरोपी बनाया गया है. उन्होंने बताया कि 25 मई को बैंक की कैशियर रितु गोयल के अचानक फरार होने के बाद बैंक द्वारा की गई आंतरिक जांच में गबन का खुलासा हुआ था. इसके बाद 29 मई को जैतापुर थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया. पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि गबन की पूरी राशि रितु गोयल ने हड़पी थी. मामले में शाखा प्रबंधक राजेश राठौर तथा बैंक कर्मचारी त्र्यंबक वाणी की संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें भी आरोपी बनाया गया. जांच में यह भी पता चला कि रितु गोयल ने गबन की अधिकांश राशि ऑनलाइन गेमिंग में खर्च कर दी, जबकि शेष रकम परिवार के साथ हवाई यात्राओं और होटलों में ठहरने पर खर्च की.

पूर्वी मप्र में तेज बारिश के आसार, भोपाल में बौछारें

नवभारत न्युज

भोपाल, 27 जुलाई. मध्यप्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव और सक्रिय मानसूनी ट्रफ के प्रभाव से मंगलवार को प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार भोपाल समेत मध्य क्षेत्र में दिनभर बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. विभाग ने कई जिलों के लिए बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी भी जारी की है.

पिछले 24 घंटे के दौरान रीवा संभाग में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई. सतना में सर्वाधिक 53.9 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुई, जबकि सीधी, खंडवा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद (नर्मदापुरम), जबलपुर और मंडला सहित कई जिलों में भी अच्छी बारिश हुई. भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और पश्चिमी मध्यप्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी दर्ज की गई. बारिश के कारण कई जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई और उमस से राहत मिली. मौसम विभाग के अनुसार उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इन क्षेत्रों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है.

> मौसम विभाग ने चेतावनी के साथ बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सतना, पन्ना, रीवा, मैहर, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में मध्यम गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. इन जिलों में एक घंटे के दौरान 5 से 15 मिमी तक वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की 30 से 60 प्रतिशत संभावना है.

कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही : कुणाल

खाद संकट और फसल खरीदी को लेकर कांग्रेस का हमला

विशेष संवाददाता

भोपाल, 27 जुलाई. प्रदेश में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि फसल खरीदी, उर्वरक उपलब्धता और कृषि कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही के कारण किसान भारी संकट का सामना कर रहे हैं.

भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कुणाल चौधरी ने कहा कि

प्रदेश में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन मूंग उत्पादन का अनुमान होने के बावजूद सरकार ने केवल 4.5 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य तय किया और अब तक मात्र 36,682 मीट्रिक टन मूंग की ही खरीदी हो सकी है. उनका आरोप था कि खरीदी की धीमी गति के कारण किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. गेहूं उत्पादकों को अपेक्षित बोनस नहीं मिला, जबकि मक्का और केला उत्पादकों को कम बाजार भाव और फसल नुकसान के कारण भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी.

> किसानों को यूरिया प्राप्त करने के लिए महंगे उर्वरक खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इसका सबसे अधिक लाभ बीमा कंपनियों को मिल रहा है. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि समर्थन मूल्य पर पूरी मूंग खरीदी सुनिश्चित नहीं की गई तो पार्टी किसान संगठनों के साथ मिलकर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी. इस दौरान पार्टी प्रवक्ता राहुल राज ने भी आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए भोपाल आ रहे किसानों को प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है और सरकार से किसानों के साथ संवाद स्थापित करने की मांग की.

33 लाख के आभूषण बरामद, 3 गिरफ्तार

उज्जैन. जिले की खाचरौद थाना पुलिस ने एक मकान में हुई लाखों रुपये की चोरी का खुलासा करते हुए लगभग 33 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं. इस मामले में मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार खाचरौद निवासी एक परिवार मुंबई घूमने गया हुआ था. इसी दौरान 18-19 जून की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए. परिजनों की शिकायत पर खाचरौद थाने में अपराध क्रमांक 268/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 एवं 331(4) में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई.

नोटिसों के बाद भी नहीं लौटी अहमदाबाद की कंपनी

18 महीने से ठप पड़ी मुलताई की सीवर परियोजना

बैतूल, 27 जुलाई. मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के मुलताई शहर की सीवर लाइन परियोजना पिछले लगभग 18 महीनों से बंद पड़ी है.

नगर पालिका परिषद की ओर से कई नोटिस जारी किए जाने और ठेकेदार कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लेने के बावजूद निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं हो सका है, जिससे शहर में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. अहमदाबाद की सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी को परियोजना के तहत लगभग एक करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य बंद पड़ा है. नगर पालिका परिषद की 13 नवंबर 2024 को आयोजित बैठक में कंपनी को 15 दिन के भीतर कार्य शुरू करने का अंतिम अवसर दिया था. परिषद ने चेतावनी दी थी कि निर्धारित अवधि में काम शुरू नहीं होने पर कंपनी की अमानत राशि जब्त कर उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी. पालिका के अभिलेखों के अनुसार सितंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच कंपनी को कई बार कार्य प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय सूचना पत्र जारी किए गए.

आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत, 10 घायल

शहडोल. जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के तीन गांवों में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई गई है। रविवार देर शाम झींक बिजुरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से धर्मेन्द्र सिंह (11) की मृत्यु हो गई। वहीं, चुटकी टोला में किशन बाई गोंड़ (28) तथा सुन्दर पाव (55) की भी बिजली गिरने से मौत हो गई। घटना के दौरान मृतकों के साथ खेत में कार्य कर रहे 10 अन्य लोग भी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर घायल हो गए.

उर्वरक वितरण व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच की मांग

भोपाल, 27 जुलाई. किसान नेता केदार शंकर सिरोही ने मध्यप्रदेश की उर्वरक वितरण व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए इसकी उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच कराने तथा पिछले 20 वर्षों के उर्वरक वितरण का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है.

सिरोही ने एक बयान में कहा कि प्रदेश में किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना कृषि विभाग की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले लगभग दो दशकों से उर्वरक वितरण व्यवस्था का संचालन मुख्य रूप से एक ही अधिकारी के माध्यम से होता रहा है और सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें संविदा व्यवस्था के तहत इस जिम्मेदारी पर बनाए रखा गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कृषि विभाग में ऐसा कोई अन्य सक्षम अधिकारी नहीं है जो इस दायित्व का निर्वहन कर सके तथा क्या पिछले 20 वर्षों में किसी वैकल्पिक व्यवस्था या उत्तराधिकारी को तैयार नहीं किया गया.

1500 तालाब बनाने के दावे पर उठे सवाल

जमीनी स्तर पर कोई बड़ी उपलब्धि दिखाई नहीं देती : अजय

भोपाल, 27 जुलाई. मध्यप्रदेश विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम में सीधी जिले में लगभग 1500 तालाब बनाए जाने के दावे पर सवाल उठाते हुए इसे तथ्यहीन बताया है.

सिंह ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि किसी भी जिले में एक साथ 1500 खेत तालाबों का निर्माण होना बड़ी उपलब्धि होती, लेकिन यदि वास्तव में इतने तालाब बने होते तो उनके अस्तित्व का प्रमाण जिले के लोगों को दिखाई देता. उन्होंने मांग की कि 'मन की बात' में उल्लेखित सभी

- पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराएं
- जनता के सामने आ सकें वास्तविक तथ्य

1500 तालाबों की वास्तविक स्थिति, संबंधित ग्राम पंचायतों के नाम, निर्माण की तिथि तथा निर्माण लागत का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए, ताकि जिले के लोग स्वयं मौके पर जाकर इन दावों का सत्यापन कर सकें. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि दिखाई नहीं देती, जिससे आशंका होती है कि तालाबों की स्वीकृतियां केवल कागजों पर जारी की गई हों और बिना वास्तविक निर्माण कार्य के भुगतान कर दिया गया हो. उन्होंने इस मामले में भ्रष्टाचार की आशंका भी व्यक्त की. सिंह ने कहा कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए, ताकि जनता के सामने वास्तविक तथ्य आ सकें.

प्रदेश में हुए 1,500 जागरुकता कार्यक्रम

विशेष संवाददाता

भोपाल, 27 जुलाई. मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी नशा मुक्ति जन-जागरुकता अभियान 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' के 12वें दिन प्रदेशभर में 1,500 से अधिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. अभियान में विभिन्न शासकीय विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों तथा स्थानीय नागरिकों की व्यापक भागीदारी देखने को मिली.

प्रदेश के बाजारों, शॉपिंग मॉल, स्कूलों, छात्रावासों, खेल मैदानों, धार्मिक स्थलों और ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पुलिस अधिकारियों ने

लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया तथा स्वयं, परिवार और समाज को नशामुक्त रखने का संकल्प दिलाया.

इंदौर में शहर पुलिस के नेतृत्व में आयोजित 10 किलोमीटर मैराथन और डिजिटल शपथ अभियान विशेष आकर्षण का केंद्र रहे. अभियान के तहत जागरुकता रथ, एलईडी डिस्प्ले, सिनेमाघरों में विशेष संदेशों का प्रदर्शन तथा एनसीसी कैडेट्स की सहभागिता के माध्यम से व्यापक जनजागरुकता फैलाई गई. भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार ने भी मैराथन में शामिल होकर युवाओं से फिटनेस अपनाने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया.

शिक्षा | आईआईटी दिल्ली के सहयोग से विद्यार्थियों को मिलेगा आधुनिक तकनीकी कौशल आधारित प्रशिक्षण

68 महाविद्यालयों में एआई कोर्स की नि : शुल्क पढ़ाई

55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में मिलेगी सुविधा

13 स्वशासी महाविद्यालयों में मिलेगी सुविधा

भोपाल, 27 जुलाई. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए महाविद्यालयों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एआई एवं फिनटेक विथ एआई के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं. इनमें 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस तथा 13 स्वशासी महाविद्यालय शामिल हैं. यह कोर्स आईआईटी दिल्ली के सहयोग से संचालित किया जाएगा.

शासकीय महाविद्यालयों में परंपरागत पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रदेश के 68 महाविद्यालयों में ड्रु और फिनटेक विथ एआई सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई कराई जाएगी. पाठ्यक्रम का संचालन IIT दिल्ली के सहयोग से किया जाएगा. इसके माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा. महाविद्यालयों में संचालित यह सर्टिफिकेट कोर्स विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह निःशुल्क होगा.

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 2000 विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं फिनटेक विथ आई के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रथम चरण में यह लक्ष्य 1000 विद्यार्थियों का था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है.

सर्टिफिकेट कोर्स से विद्यार्थियों को लाभ

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से संचालित एआई और फिनटेक विथ एआई सर्टिफिकेट कोर्स का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है. इससे वे नई तकनीकों का प्रभावी उपयोग करते हुए नवाचार और डिजिटल युग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें. इससे विद्यार्थियों को करियर में नए अवसर मिलेंगे. वर्तमान के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और फिनटेकका महत्व लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में एआईऔर फिनटेक विथ एआई सर्टिफिकेट कोर्सविद्यार्थियों के लिए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कौशल-विकास कार्यक्रम बनकर उभर रहा है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14